



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 24 मार्च, 2022

चैत्र 3, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 63/ग्यारह-2-22-9(42)/17-टी0सी0 60-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (229)-2022

लखनऊ, 24 मार्च, 2022

अधिसूचना

प0आ0-62

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

### उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौवनवां संशोधन) नियमावली, 2022

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौवनवां संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 29 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में,- नियम 36 में, उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम तारीख 1 जनवरी, 2022 से रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	नियम 36 का संशोधन

	<p>“(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे इन्वॉइस या डेविट नोट्स, जिनका ब्यौरा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दिया जाना अपेक्षित हो, से संबंधित कोई इनपुट कर प्रत्यय तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि-</p> <p>(क) ऐसे इन्वॉइसेस या डेविट नोट्स का ब्यौरा पूर्तिकर्ता द्वारा प्रपत्र जीएसटीआर-1 में बाह्य पूर्ति से संबंधित विवरण में न दे दिया गया हो या ऐसे इनवाइस सुविधा देने का प्रयोग न किया गया हो; और</p> <p>(ख) ऐसे इन्वॉइसेस या डेविट नोट्स का ब्यौरा नियम 60 के उपनियम (7) के अधीन प्रपत्र जीएसटीआर-2ख में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को न प्रेषित कर दिया गया हो।”;</p>
नियम 80 का संशोधन	<p>3-उक्त नियमावली में, नियम 80 में, -</p> <p>(क) उपनियम 1 के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-</p> <p>“(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 को या इसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”;</p> <p>(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“(3क) उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये उक्त स्व-प्रमाणित समाधान विवरण, तारीख 28 फरवरी, 2022 को या इसके पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा”;</p>
नियम 95 का संशोधन	<p>4-उक्त नियमावली में, नियम 95 में, उपनियम (3) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा तथा वह तारीख 1 अप्रैल, 2021 से बढ़ा हुआ समझा जायेगा; अर्थात् :-</p> <p>“परन्तु यह कि जहां आवेदक की विशिष्ट पहचान संख्या कर इनवाइस में उल्लिखित न हो, वहाँ ऐसे बीजक पर आवेदक द्वारा संदत कर का प्रतिदाय केवल तभी किया जायेगा, जब इनवाइस की प्रति, आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई हो और प्रपत्र जीएसटीआरएफडी-10 में प्रतिदाय आवेदन के साथ दाखिल की गई हो।”;</p>
नियम 142 का संशोधन	<p>5-उक्त नियमावली में, नियम 142 में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से,-</p> <p>(क) उपनियम (3) में, शब्द और अक्षर “माल और प्रवहण को निरुद्ध करने या जब्त करने के 14 दिनों” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के 7 दिनों के भीतर किन्तु उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व” रख दिये जायेंगे;</p>

<p>(ख) उपनियम (5) में, शब्द “कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, व्याज और शास्ति” के स्थान पर शब्द “उससे संबंधित व्यक्ति द्वारा यथास्थिति संदेय कर, व्याज और शास्ति,” रख दिये जायेंगे ;</p>	
<p>6-उक्त नियमावली में, नियम 144 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम, तारीख 1 जनवरी, 2022 से बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p><b>“अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली—144क.</b> (1) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उक्त धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण के बाजार मूल्य की सूची तैयार करके और उसका प्राक्कलन करके इस प्रकार प्रतिधारित या अभिगृहीत किए गए माल या प्रवहण के विक्रय या निपटान के लिए अग्रसर होगा :</p> <p>परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल नैसर्गिक रूप से नाशवान या परिसंकटमय हो या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा ।</p> <p>(2) उक्त माल या प्रवहण का विक्रय नीलामी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, किया जाएगा, जिसके लिए विक्रय किए जाने वाले माल या प्रवहण और विक्रय के प्रयोजन को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए <b>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10</b> में नोटिस जारी किया जाएगा :</p> <p>परंतु जहां उक्त माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपनियम (1) में वर्णित समयावधि के पश्चात्, किंतु इस उपनियम के अधीन नोटिस जारी किए जाने से पूर्व, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का, जिसमें ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन पर उपगत कोई व्यय भी है, संदाय करता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करेगा और ऐसे माल या प्रवहण को निर्मुक्त करेगा ।</p> <p>(3) बोली प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख या नीलामी की तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व का नहीं होगा :</p> <p>परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल नैसर्गिक रूप में नाशवान या परिसंकटमय हो या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना हो, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा ।</p>	<p>नियम 144 का संशोधन</p>

	<p>(4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व बोली निक्षेप की रकम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस की जा सकेगी, उस दशा में समपहत की जा सकेगी जब सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में विफल रहता है।</p> <p>(5) समुचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा करते हुए, <b>प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-11</b> में नोटिस जारी करेगा :</p> <p>परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल नैसर्गिक रूप में नाशवान या परिसंकटमय हो या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना हो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा।</p> <p>(6) समुचित अधिकारी, बोली की पूर्ण रकम का संदाय किए जाने पर, उक्त माल या प्रवहण का स्वामित्व और कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा और <b>प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-12</b> में प्रमाणपत्र जारी करेगा।</p> <p>(7) समुचित अधिकारी, वहां प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः नीलामी के लिए अग्रसर होगा, जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या पर्याप्त सहभागिता की कमी के कारण या निम्न बोलियों के कारण नीलामी को अप्रतिस्पर्धात्मक समझा जाता है।</p> <p>(8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपील फाइल की गई हो वहां इस नियम के अधीन अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई समझी जाएगी :</p> <p>परंतु यह उपनियम नाशवान या परिसंकटमय प्रकृति के माल के संबंध में लागू नहीं होगा।”</p>
नियम 154 का संशोधन	<p>7-उक्त नियमावली में, नियम 154 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम, तारीख 1 जनवरी, 2022 से रख दिया जायेगा, अर्थात् :-</p> <p><b>“माल या प्रवहण और जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन</b></p> <p><b>154</b> (1) व्यतिक्रमी से देयों की वसूली के लिए या धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए माल या प्रवहण, चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई रकम,-</p> <p>(एक) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के सापेक्ष विनियोजित की जाएगी;</p> <p>(दो) तत्पश्चात् यथास्थिति धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम या उसके अधीन संदेय शास्ति के संदाय के सापेक्ष विनियोजित की जाएगी;</p>

<p>(तीन) तत्पश्चात् इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यक्तिक्रमी से देय किसी अन्य रकम के सापेक्ष विनियोजित की जाएगी; और</p> <p>(चार) अतिशेष, यदि कोई हो, यथास्थिति, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और जहां उक्त व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित न है वहां उक्त रकम संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी ;</p> <p>(2) उप-नियम (1) के खंड (घ) के अनुसार, जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमो का अतिशेष का संदाय करना संभव न हो वहां विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा ।</p>	
<p>8-उक्त नियमावली में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से नियम 159 में-</p> <p>(क) उपनियम (2) में,-</p> <p>(अ) शब्द “कुर्की के आदेश की प्रति” के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक “प्रपत्र जीएसटीडीआरसी-22 में” बढ़ा दिये जाएंगे;</p> <p>(आ)शब्द “जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा ।” के पश्चात् शब्द और अंक “और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्क की गई हो ।” बढ़ा दिये जाएंगे ;</p> <p>(ख) उपनियम (3) में-</p> <p>(अ) शब्द “और यदि कराधेय व्यक्ति” के स्थान पर शब्द “और यदि व्यक्ति, जिसकी संपत्ति कुर्क की गई हो” रख दिये जायेंगे;</p> <p>(आ)शब्द “कराधेय व्यक्ति” के स्थान पर शब्द “ऐसे व्यक्ति” रख दिये जायेंगे;</p> <p>(ग) उपनियम (4) में, दो स्थानों पर आने वाले शब्द “कराधेय व्यक्ति” के स्थान पर शब्द “ऐसे व्यक्ति” रख दिये जायेंगे;</p> <p>(घ) उपनियम (5) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “कुर्की के सात दिवसों के भीतर उपनियम (1) के अधीन इस आशय की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा” के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक “प्रपत्र जीएसटीडीआरसी-22क में एक आपत्ति फाइल कर सकेगा” रख दिये जायेंगे;</p>	नियम 159 का संशोधन

प्रपत्र जीएसटी डीआरसी - 10 का संशोधन	9-उक्त नियमावली में, "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-10" के स्थान पर तारीख 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात् :-								
	<p align="center"><b>"प्रपत्र जीएसटी डीआरसी - 10</b></p>								
	<p align="center">[नियम 144 (2) और 144क देखिए]</p>								
	<p align="center"><b>अधिनियम की धारा 79(1) (ख) या धारा 129(6) के अधीन निलामी के लिए नोटिस</b></p>								
	मांग आदेश सं.								
	अवधि :								
	मेरे द्वारा ---- रुपए और उस पर ब्याज पर की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए गए या कर स्थगित किए गए माल के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में वसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यय ग्राह्य है।								
	या								
	धारा 129 के अधीन प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय.....रुपए की शास्ति की वसूली तथा ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा में उपगत व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए धारा 129 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार विक्रय या निपटान के लिए दायी है।								
	विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जायेगा और माल तथा/या प्रवहण अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखा जाएगा। विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, शीर्षक और हितों के लिए किया जायेगा और उक्त संपत्तियों के लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार वे सुनिश्चित किये गये हैं प्रत्येक लाट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।								
यह निलामी..... को प्रातः/सायं.....बजे आयोजित की जाएगी।									
प्रत्येक लाट की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार संदत्त की जाएगी और संदाय के व्यतिक्रम में माल और/ या प्रवहण को पुनः निलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा।									
<p align="center"><b>अनुसूची</b></p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>माल या प्रवहण का विवरण</th> <th>मात्रा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	क्रम संख्या	माल या प्रवहण का विवरण	मात्रा	1	2	3			
क्रम संख्या	माल या प्रवहण का विवरण	मात्रा							
1	2	3							
स्थान:									
तारीख:									
हस्ताक्षर									
नाम:									
पदनाम: " ;									

<p>10-उक्त नियमावली में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-11 में-</p> <p>(क) शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "नियम 144 (5) और 147 (12) देखिए" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिए" रख दिये जाएंगे;</p> <p>(ख) शब्द "माल" के स्थान पर शब्द "माल या प्रवहण" रख दिये जाएंगे;</p>	<p>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11 का संशोधन</p>
<p>11-उक्त नियमावली में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-12 में-</p> <p>(क) शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "नियम 144 (5) और 147 (12) देखिए" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिए" रख दिये जाएंगे ;</p> <p>(ख) शब्द "माल" जहां कहीं भी आते हैं के स्थान पर शब्द "माल या प्रवहण" रख दिये जाएंगे ;</p> <p>(ग) शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "धारा 79 (1) (ख)/(घ) के उपबंधों" के पश्चात् शब्द, अंक और कोष्ठक "या धारा 129 (6)" बढ़ा दिये जाएंगे ;</p>	<p>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 का संशोधन</p>
<p>12-उक्त नियमावली में, "प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-22" के स्थान पर, तारीख 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्रपत्र रख दिये जाएंगे, अर्थात् :-</p> <p style="text-align: center;"><b>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22</b></p> <p style="text-align: center;">[नियम 159 (1) देखिए]</p> <p>संदर्भ संख्या.: _____ तारीख: _____</p> <p>सेवा में,</p> <p>नाम.....</p> <p>पता.....</p> <p>(बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था/स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकृत करने वाला प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी)</p> <p style="text-align: center;"><b>धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की</b></p> <p>यह सूचित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(नाम) जिनका .....(पता) पर कारबार का मुख्य स्थान है जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या.....(जीएसटीआईएन/आईडी), पैर रजिस्ट्रीकृत कराधेय है।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>यह सूचित किया जाता है कि श्री.....(नाम) निवासी.....(पता) जिनकी पैर संख्या.....और/या आधार संख्या.....है, धारा 122 की उप-धारा (1क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति है।</p> <p>उक्त अधिनियम की धारा.....के अधीन उक्त व्यक्ति पर देय कर या किसी</p>	<p>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 का संशोधन</p>

	<p>अन्य रकम को अवधारित करने के लिए पूर्वोक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं। विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -</p> <p>&lt;&lt;वचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता आपके बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था में है जिसका &lt;&lt;खाता संख्या&gt;&gt;..... है।</p> <p>या</p> <p>.....पर अवस्थित संपत्ति की संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति&gt;&gt;।</p> <p>या</p> <p>यान संख्या..... &lt;&lt;वर्णन&gt;&gt;</p> <p>या</p> <p>अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..... &lt;&lt; (वर्णन) &gt;&gt;</p> <p>राजस्व के हितों को संरक्षित करने के लिए तथा अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं.....(नाम), .....(पदनाम) पूर्वोक्त खाता/संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता हूँ।</p> <p>इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना इसी पैन संख्या पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा प्रचालित उक्त खाते या किसी अन्य खाते से कोई भी विकलन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।</p> <p>या</p> <p>ऊपर वर्णित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपटान हेतु अनुज्ञात नहीं की जाएगी।</p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर नाम पदनाम</p> <p>प्रति (व्यक्ति का नाम) ;</p>
<p>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 का संशोधन</p>	<p>13-उक्त नियमावली में, प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-23 में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से, -</p> <p>(क)शब्द “/स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी”, के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी” ;</p> <p>(ख) दोनों स्थानों पर आने वाले, शब्द “कोई कार्यवाहियाँ व्यक्तिगत व्यक्ति के विरुद्ध लंबित” के स्थान पर, शब्द “अपेक्षित”, रख दिये जायेंगे ;</p>



14-उक्त नियमावली में, प्रपत्र एपीएल-01 में, प्रविष्टि संख्या 15 में, खंड (क) के अधीन सारणी के स्थान पर, तारीख 1 जनवरी, 2022 से, निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात् :-							प्ररूप एपीएल-01 का संशोधन	
“विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम		
(क) स्वीकृत रकम	कर/उपकर					< योग>		
	ब्याज					< योग>		
	शास्ति					< योग>		
	फीस					< योग>		
	अन्य प्रभार					< योग>		
(ख) पूर्व जमा (सीजी एसटी, एसजी एसटी या उपकर के संबंध में विवादित कर/उपकर का 10 % किन्तु 25 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक नहीं, या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपए	कर/ उपकर					< योग>		

	“विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम										
	(ग)धारा 129 की उपधारा (3) के मामले में पूर्व जमा	शास्ति					< योग >										
प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 का संशोधन	<div>15-उक्त नियमावली में, प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र तारीख 1 जनवरी, 2022 से बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-</div> <div>“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22ए”</div> <div>[नियम 159 (5) देखें]</div> <div>तारीख :</div> <div>संदर्भ संख्या</div> <div>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश की एआरएन संख्या</div> <div>सेवा में,</div> <div>प्रधान आयुक्त/आयुक्त</div> <div>.....(अधिकारिता)</div> <div>संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरुद्ध आपत्ति फाइल करने के लिए आवेदन</div> <div>एआरएन संख्या.....द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश जारी किया गया है।</div> <table><tr><td>संदर्भ पहचान संख्या</td><td></td></tr><tr><td>अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति</td><td>&lt;&lt; संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति&gt;&gt;</td></tr><tr><td>अनंतिम रूप से कुर्क खाता</td><td>&lt;&lt;बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या&gt;&gt;</td></tr><tr><td>अनंतिम रूप से कुर्क यान</td><td>&lt;&lt; यान के ब्यौरे&gt;&gt;</td></tr><tr><td>कोई अन्य संपत्ति</td><td>&lt;&lt; ब्यौरे&gt;&gt;</td></tr></table> <div>2. सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 159 (5) के उपबंधों के अनुसार, मैं निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता हूं।</div> <div>&lt;&lt;..... &gt;&gt;</div> <div>&lt;&lt;..अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज..&gt;&gt;</div> <div>सत्यापन</div> <div>मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</div> <div>नाम-</div> <div>जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में) –</div>							संदर्भ पहचान संख्या		अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति	<< संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>>	अनंतिम रूप से कुर्क खाता	<<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या>>	अनंतिम रूप से कुर्क यान	<< यान के ब्यौरे>>	कोई अन्य संपत्ति	<< ब्यौरे>>
संदर्भ पहचान संख्या																	
अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति	<< संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>>																
अनंतिम रूप से कुर्क खाता	<<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या>>																
अनंतिम रूप से कुर्क यान	<< यान के ब्यौरे>>																
कोई अन्य संपत्ति	<< ब्यौरे>>																

<p>पैन और / या आधार संख्या (अन्य के मामलों में) –</p> <p>स्थान –</p> <p>तारीख –</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर” ।</p>	
---	--

आज्ञा से,  
संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 63/XI-2-22-9(42)-17-T.C.60-U.P.GST Rules-2017-Order(229)-2022, dated March 24, 2022:

No. 63/XI-2-22-9(42)-17-T.C.60-U.P.GST Rules-2017-Order(229)-2022

*Dated Lucknow, March 24, 2022*

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

**Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty Fourth Amendment) Rules, 2022**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty Fourth Amendment) Rules, 2022.	Short title and commencement
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force from 29 <sup>th</sup> day of December 2021.	
2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred to as the said rules), — in rule 36, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, with effect from the 1 <sup>st</sup> day of January, 2022, namely: - “(4) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes the details of which are required to be furnished under sub-section (1) of section 37 unless,- (a) the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in <b>FORM GSTR-1</b> or using the invoice furnishing facility; and (b) the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in <b>FORM GSTR-2B</b> under sub-rule (7) of rule 60.”;	Amendment of rule 36
3. In the said rules, in rule 80,— a. after sub-rule (1), the following sub-rule shall be <i>inserted</i> , namely:- “(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), for the financial year 2020-2021 the said annual return shall be furnished on or before the twenty-eighth day of February, 2022.”; b. after sub-rule (3), the following sub-rule shall be <i>inserted</i> , namely:- “(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), for the	Amendment of rule 80

	financial year 2020-2021 the said self-certified reconciliation statement shall be furnished along with the said annual return on or before the twenty-eighth day of February, 2022.”;
Amendment of rule 95	<p>4. In the said rules, in rule 95, in sub-rule (3), after clause (c), the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2021, namely:-</p> <p>“<b>Provided</b> that where Unique Identity Number of the applicant is not mentioned in a tax invoice, the refund of tax paid by the applicant on such invoice shall be available only if the copy of the invoice, duly attested by the authorized representative of the applicant, is submitted along with the refund application in <b>FORM GST RFD-10</b>.”;</p>
Amendment of rule 142	<p>5. In the said rules, in rule 142, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022,–</p> <p>a. in sub-rule (3), for the words and letters, “fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance”, the words, brackets and figures, “seven days of the notice issued under sub-section (3) of Section 129 but before the issuance of order under the said sub-section (3)” shall be substituted;</p> <p>b. in sub-rule (5), for the words, “tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax”, the words, “tax, interest and penalty, as the case may be, payable by the person concerned” shall be substituted;</p>
Amendment of rule 144	<p>6. In the said rules after rule 144, the following rule shall be inserted with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022, namely:-</p> <p>“<b>Recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit.- 144A.</b> (1) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) of section 129 within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3) of the said section 129, the proper officer shall proceed for sale or disposal of the goods or conveyance so detained or seized by preparing an inventory and estimating the market value of such goods or conveyance:</p> <p><b>Provided</b> that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.</p> <p>(2) The said goods or conveyance shall be sold through a process of auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in <b>FORM GST DRC-10</b> clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sale:</p> <p><b>Provided</b> that where the person transporting said goods or the owner of such goods pays the amount of penalty under sub-section (1) of section 129, including any expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance, after the time period mentioned in sub-rule (1) but before the issuance of notice under this sub-rule, the proper officer shall cancel the process of auction and release such goods or conveyance.</p> <p>(3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2):</p> <p><b>Provided</b> that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.</p> <p>(4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to</p>

<p>participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.</p> <p>(5) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in <b>FORM GST DRC-11</b> requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction:</p> <p><b>Provided</b> that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.</p> <p>(6) On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession and ownership of the said goods or conveyance to the successful bidder and issue a certificate in <b>FORM GST DRC-12</b>.</p> <p>(7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.</p> <p>(8) Where an appeal has been filed by the person under the provisions of sub-section (1) read with sub-section (6) of section 107, the proceedings for recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit under this rule shall be deemed to be stayed:</p> <p><b>Provided</b> that this sub-rule shall not be applicable in respect of goods of perishable or hazardous nature.”;</p>	
<p>7. In the said rules, for rule 154, the following rule shall be substituted with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022, namely:—</p> <p><b>“Disposal of proceeds of sale of goods or conveyance and movable or immovable property.—</b></p> <p><b>154.</b> (1) The amounts so realised from the sale of goods or conveyance, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter or for recovery of penalty payable under sub-section (3) of section 129 shall,—</p> <p>i. first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;</p> <p>ii. next, be appropriated against the amount to be recovered or to the payment of the penalty payable under sub-section (3) of section 129, as the case may be;</p> <p>iii. next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made there under; and</p> <p>iv. the balance, if any, shall be credited to the electronic cash ledger of the owner of the goods or conveyance as the case may be, in case the person is registered under the Act, and where the said person is not required to be registered under the Act, the said amount shall be credited to the bank account of the person concerned;</p> <p>(2) where it is not possible to pay the balance of sale proceeds, as per clause (d) of sub-rule (1), to the person concerned within a period of six months from the date of sale of such goods or conveyance or such further period as the proper officer may allow, such balance of sale proceeds shall be deposited with the Fund;</p>	<p>Amendment of rule 154</p>
<p>8. In the said rules, in rule 159, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022,—</p> <p>(a) in sub-rule (2)-</p>	<p>Amendment of rule 159</p>

	<p>(A) after the words “copy of the order of attachment”, the words, letters and figures “in <b>FORM GST DRC-22</b>” shall be inserted;</p> <p>(B) after the words “Commissioner to that effect.”, the words and figures, “and a copy of such order shall also be sent to the person whose property is being attached under section 83” shall be inserted;</p> <p>(b) in sub-rule (3)-</p> <p>(A) for the words “and if the taxable person”, the word “and if the person, whose property has been attached,” shall be substituted;</p> <p>(B) for the words “by the taxable person”, the words, “by such person” shall be substituted;</p> <p>(c) in sub-rule (4), for the words “the taxable person” occurring at both the places, the words “such person” shall be substituted;</p> <p>(d) in sub-rule (5), for the words brackets and figure “, within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection”, the words, letters and figures “file an objection in <b>FORM GST DRC-22A</b>” shall be substituted;</p>
Amendment of FORM GST DRC-10	<p>9. In the said rules, for “<b>FORM GST DRC-10</b>”, the following form shall be substituted, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022, namely:—</p> <p style="text-align: center;"><b>“FORM GST DRC – 10</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[See rule 144(2)&amp;144A]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Notice for Auction under section 79 (1) (b) or section 129(6) of the Act</b></p> <p>Demand order no.: _____ Date: _____</p> <p>Period: _____</p> <p>Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs. .... and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Whereas the goods or conveyance detained or seized under Section 129 are liable for sale or disposal in accordance with the provisions of sub-section (6) of Section 129 for recovery of penalty of Rs. .... payable under sub-section (3) of section 129 and the expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance and other administrative expenses</p> <p>The sale will be by public auction and the goods and/or conveyance shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.</p> <p>The auction will be held on ..... at .... AM/PM.</p> <p>The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods and/or conveyance shall be again put up for auction and resold.</p>

Schedule			
Serial No.	Description of goods or conveyance	Quantity	
1	2	3	
Place:		Signature	
Date:		Name	
		Designation: "	
<p>10. In the said rules, in <b>FORM GST DRC-11</b>, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022, -</p> <p>a. for the words, figures, letter and brackets "See rule 144(5) &amp; 147(12)", the words, figures and brackets "See rule 144(5),144A and 147(12)" shall be substituted;</p> <p>b. for the word "goods", the words "goods or conveyance" shall be substituted;</p>			Amendment of FORM GST DRC-11
<p>11. In the said rules, in <b>FORM GST DRC-12</b>, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022-</p> <p>a. for the words, figures, brackets and letter "See rule 144(5) &amp; 147(12)", the words, figures and brackets "See rule 144(5),144A and 147(12)" shall be substituted;</p> <p>b. for the word "goods", wherever it occurs, the words "goods or conveyance" shall be substituted;</p> <p>c. after the words, figures, brackets and letters "provisions of section 79(1)(b)(d)", the words, figures and brackets "or section 129(6)" shall be inserted;</p>			Amendment of FORM GST DRC-12
<p>12. In the said rules, for <b>FORM GST DRC-22</b>, the following form shall be substituted, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022, namely:-</p> <p style="text-align: center;"><b>"FORM GST DRC -22</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[See rule 159(1)]</i></p> <p>Reference No.:</p> <p>To</p> <p>Name</p> <p>Address</p> <p>(Bank/ Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority)</p> <p style="text-align: center;"><b>Provisional attachment of property under section 83</b></p> <p>It is to inform that M/s ----- (name) having principal place of business at -----</p> <p>----- (address) bearing registration number as ----- (GSTIN/ID), PAN is a registered taxable person under the &lt;&lt;SGST/CGST&gt;&gt; Act.</p>			Amendment of FORM GST DRC-22

	<p>or</p> <p>It is to inform that Sh.....(name) resident of.....(address) bearing PAN .....and/or Aadhaar No. .... is a person specified under sub-section (1A) of Section 122 .</p> <p>-----Proceedings have been launched against the aforesaid person under section &lt;&lt;&gt;&gt; of the said Act to determine the tax or any other amount due from the said person. As per information available with the department, it has come to my notice that the said person has a -</p> <p>&lt;&lt;saving / current / FD/RD / depository &gt;&gt;account in your &lt;&lt; bank/post office/financial institution&gt;&gt; having account no. &lt;&lt; A/c no. &gt;&gt;;</p> <p>or</p> <p>property located at &lt;&lt; property ID &amp; location&gt;&gt;.</p> <p>or</p> <p>Vehicle No. .... &lt;&lt;description&gt;&gt;</p> <p>or</p> <p>Others (please specify) ..... &lt;&lt;description&gt;&gt;</p> <p>In order to protect the interests of revenue and in exercise of the powers conferred under section 83 of the Act, I ----- (name), ----- (designation), hereby provisionally attach the aforesaid account / property.</p> <p>No debit shall be allowed to be made from the said account or any other account operated by the aforesaid person on the same PAN without the prior permission of this department.</p> <p>or</p> <p>The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the prior permission of this department.</p> <p style="text-align: right;">Signature Name Designation</p> <p>Copy to (person)”</p>
Amendment of FORM GST DRC-23	<p>13. In the said rules, in <b>FORM GST DRC-23</b>, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022,—</p> <p>a. after “/Immovable property registering authority”, the following shall be inserted, namely:—</p> <p>“/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority”;</p> <p>b. for the words “proceedings pending against the defaulting person which warrants the”, occurring at both the places, the words, “requirement of” shall be substituted;</p>
Amendment of FORM APL-01	<p>14. In the said rules, in <b>FORM APL-01</b>, in entry number 15, for the table under clause(a), the following table shall be substituted, with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022, namely:—</p>



Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total amount	
(a) Admitted amount	Tax/ Cess					< total >	< total >
	Interest					< total >	
	Penalty					< total >	
	Fees					< total >	
	Other charges					< total >	
(b) Pre-deposit (10% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess, or not exceeding Rs. 50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess)	Tax/ Cess					< total >	
(c) Pre-deposit in case of sub-section (3) of section 129	Penalty					< total >;	

15. In the said rules, after **FORM GST DRC-22**, the following form shall be inserted with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022, namely:-

**“FORM GST DRC – 22A**

[See rule 159(5)]

Reference No.:                      Date:

ARN No. of Order in FORM GST DRC-22:

To  
The Pr. Commissioner/Commissioner  
.....(Jurisdiction)

**Application for filing objection against provisional attachment of property**

Whereas, an order in FORM GST DRC-22 has been issued for provisional attachment of the following property under the provisions of section 83 of the Act vide ARN No.....

Amendment of  
FORM GST  
DRC-22

Ref ID	
Property provisionally attached	<< property id & location>>
Account provisionally attached	<<saving/current/FD/RD/ depository account no>>
Vehicle provisionally attached	<<Vehicle details>>
Any other property	<<details >>

2. In accordance with the provisions of Rule 159(5) of the CGST Rules, 2017, I hereby submit my objection on the basis of following facts and circumstances.

.

<<.....>>

<<...Documents to be uploaded...>>

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Name-

GSTIN (in case of registered person)-

PAN and/or Aadhaar No. (in case of others)-

Place –

Date –

Signature of Authorized Signatory”.

By order,  
SANJIV MITTAL,  
*Apar Mukhya Sachiv.*